

भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे गेम्स

ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एजीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में आईओए की प्रेसिडेंट पीटी ऊषा ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किया साइन

ओलिंपिक गेम्स 2036 की दावेदारी मजबूत होगी

नई दिल्ली/ए। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एजीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली इन गेम्स का आयोजन किया था। अब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल



20 साल बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट

- 20 साल के बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा
- पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन
- सोडब्रूथरी के अलावा, भारत 1951 और 1982 एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका
- 2003 में हैदराबाद में एफो-एशियन कप का आयोजन भी हुआ था

ओलिंपिक-2036 की दावेदारी मजबूत होगी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलिंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत 2036 के ओलिंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसे इसका ऐलान किया था। पिछले साल तबड़ में भारत ने ओलिंपिक गेम्स-2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की थी।

अहमदाबाद के अलावा अबुजा भी था दौड़ में शामिल

पिछले महीने रायपुरमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की सिफारिश की थी। अब ग्लासगो में हुई आमसभा की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन भारत बाजी मारने में सफल रहा। रायपुरमंडल खेल को 2030 में 100 साल भी पूरे होने का रहे है, ऐसे में इस ऐतिहासिक मौके पर भारत में इन खेलों का आयोजन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

जोते थे।
कॉमनवेल्थ की टीम दो बार गुजरात का दौरा कर चुकी। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए विररवस्तरय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से रायपुर 6

आज बेबाक

बैंगल में एसआईआर से यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौरा गई हैं। वहां से रौलेट्वा और बंगलादेशी घुसपैठिया डर कर भाग रहे हैं। इससे ममता दीदी का वोट बैंक खराब हो रहा है और उनकी राजनीतिक दृढ़तादृष्टी के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। नतीजतन दीदी अब यादगिरा पर उतर आई हैं। उन्होंने सोधे केन्द्र सरकार को धमकी दी है कि एसआईआर से उनके वोट बैंक पर आंच आई तो वे पूरे भारत देश को हिलाल कर देंगे। इस तरह की गौड़भभकी देने वाली दीदी यह समझ ले कि भीगी बिल्लियों के छत्रिने से पहाड़ नहीं गिरा करते।

राज्य वीरता पुरस्कार: बहादूर बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी 25 हजार नकद इनाम

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के बच्चों को किसी विशेष घटना में प्रदर्शित उनके अद्वय प्रभाव, बुद्धिमान और वीरता के सम्मान में 'राज्य वीरता पुरस्कार वर्ष 2025' प्रदान करने जा रही है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 बालक/बालिकाओं को 25 हजार रुपए नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार से संबंधित ज्ञाता जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर पुलिस मुख्यालय परिसर, जी. ई. रोड, रायपुर स्थित कार्यालय से सूचना पटल पर 20 दिसंबर तक देहांत जा सकती है। इच्छुक आवेदक अपनी प्रतिक्रियाएं 20 दिसंबर तक जिला कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं।

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या की

नई दिल्ली/ए। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल विश्वोरा चौधरीया की बहू दीपिका चौधरीया (38) ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दीपिका का शव ड्रेडिंग रूम के पंखे से लटकता हुआ मिला। दीपिका का शव सबसे पहले उसके पिता हरप्रताप चौधरीया ने देखा। हरप्रताप उन्हें लेकर अस्पताल गए, जहां दीपिका को मृत घोषित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीपिका ने अपने पिता के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीपिका ने डायरी में लिखा, 'आम किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है।'

विदेश भेजने वाले पैसे से 10% से ज्यादा नहीं काट सकते टीडीएस :सुको

नई दिल्ली। सुकोम कोट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना है। सुकोट कानून है कि यदि संबंधित देश के साथ भारत का संबंध टैक्स एडवॉकेट एग्रीमेंट है तो अतिरिक्त भारतीय या विदेशी कर्मचारियों को भेजी जाने वाली भ्रमराशि पर टीडीएस 10% से अधिक काटा जा सकता है। यह फैसला उन मामलों पर लागू होगा, जहां विदेशी प्रायोजकों डीटीएस के लाभ लेने के योग्य हैं। अदालत ने कहा कि यदि डीटीएस में अधिकतम टैक्स 10% तक है, तो आकर्षक विभाग 20% टीडीएस की मंगनी नहीं कर सकता। नतीजतन ही विदेशी कंपनी या प्रायोजकों ने पैन उपलब्ध न कराया हो।

संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ, विश्व के लिए उदाहरण: राष्ट्रपति मुर्मू

भारतीय संसद, विश्व के अनेक लोकतंत्रों के लिए उदाहरण

नई दिल्ली(वातां)। राष्ट्रपति डीपी मुर्मू ने संविधान को राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान का ग्रंथ बताते हुए कहा है कि विश्व दायक में हमारी संसद इसकी मूल्यों पर चलते हुए इन अनेकानेकों को अभिव्यक्त करने के अनेक कार्य करेगी। मुर्मू ने बुधवार को यहां संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में अपने अभिभाषण में कहा कि संविधान कक्षा ने संसदीय प्रणाली को अपनेने के पक्ष में जो ठोस तर्क दिये गए थे वे आज भी प्रासंगिक हैं। विश्व



के विशालतम लोकतंत्र में जन-आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद, विश्व के अनेक लोकतंत्रों के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा, 'हमारे संविधान निर्माता' ■ शेष पृष्ठ 6

संविधान दिवस: मोदी ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखने पर दिया जोर

भारत अब 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा

नई दिल्ली (वातां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नागरिकों से अपील की है कि अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखें क्योंकि भारत एक एक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को यह शिक्षण 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाया जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रति में अहमिती स्थायी प्रमाण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015



में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे संविधान ने समाज पर प्रभुत्व के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर पर ■ शेष पृष्ठ 6

संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा भारत : मुख्यमंत्री साय

संविधान की प्रस्तावना का किया सामूहिक वाचन

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 75वें संविधान दिवस के अवसर पर रायपुरी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और

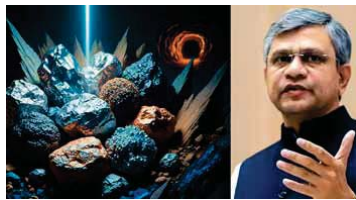


जनसंविधानियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सचेतनी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सर्वप्रथम संविधान में आस्था रखता हुआ आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रलेख ■ शेष पृष्ठ 6

केन्द्रीय कैबिनेट : दुर्लभ धातुओं पर सरकार का बड़ा कदम

मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने 7,280 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली/आईएसएस। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 19,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैनेजेंट निर्माण योजना शामिल है, जो पेट्रोकेमिकल प्लांटों और रक्षा क्षेत्र के लिए आयु मानी जा रही है।



चीन का दबाव और भारत की रणनीति

एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत से उपग्रहों के लिए दुर्लभ पृथ्वी मैनेजेंट के निर्माण के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जता दिए हैं, लेकिन भारतीय कर्मचारियों को अब तक कोई लक्ष्य नहीं मिला है। अब तक की यात्रा माला लगभग 2,000 टन ऑक्साइड है।

वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70% और प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा निर्यात करता है, जो पहले के 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से लगभग तीन गुना अधिक है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन ने निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। चीन

इन परियोजनाओं को हरी झंडी

- 7,280-रुपए अर्ध परमाण्वीय मैनेजेंट निर्माण योजना
- 1,457-रुपए निर्माण द्वारा (ओषा) - कनालास रेलवे लाइन का दोहरीकरण
- 9,859-मुद्रों नेटो का विस्तार
- 1,324-बदलाव - कर्जत तीसरी और चौथी लेवेल लाइन

19,919-सौ परियोजनाओं पर कुल आवंटन, राशि आवंटन (करोड़)

चुम्बकों में बदलने की प्रक्रिया शामिल होगी। योजना पर लगभग 7,200 करोड़ का निवेश होगा। इसके तहत 1,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का सुजन और 1,200 एमटीएम क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। योजना की अवधि कुल 7 वर्ष होगी, जिसमें निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में होता है। भारत में इस क्षेत्र को अभी भी श्री सीमित फंडिंग, ■ शेष पृष्ठ 6

माओवाद को बड़ा झटका, 41 कैडरों ने छोड़ी बंदूक, मुख्यधारा में लौटे



बीजापुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के

नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बुधवार को माओवादियों को करा झटका लगा। कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम था। इसमें 12 महिलाएं और 29 पुरुष हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें पोखरीजी

आत्मसमर्पण करने

वालों में कई बड़े नाम पोखरीजी बटालियन-1 के 5 सदस्य, 3 परिया कमेटी मेंबर, कई प्लाटून कमांडर, मिलिशिया कमांडर और जनता सरकार के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं।

बटालियन-1 के 5 सदस्य, 3 परिया कमेटी

मेंबर, कई प्लाटून कमांडर, मिलिशिया कमांडर और जनता सरकार के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं।

टक-स्कॉपियों में मिंडाट 2 जवान समेत 5 की मौत पर हुई मौत

जांजगीर-चांपा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़

के जांजगीर-चांपा जिले में भीषण संघर्ष के दौरान 2 जवान समेत 5 की मौत पर हुई मौत। हत्यारे 49 पर सुकाली के पास टक और स्कॉपियों की जोड़कर भिड़ते हुए थे। हत्यारे इन भीषण था कि कर में सवार 5 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 भारतीय सेना के जवान भी शामिल हैं। इसमें 1 जवान की 8 दिन पहले शादी हुई थी। हत्यारे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा सभी बरात में शामिल होकर वापस नवाब लौट रहे थे। दुर्घटना मंगलवार और बुधवार के दरमियानी रात करीब 1 बजे हुई। सुकाली के पास रायपुर की ओर बिलासपुर जा रही टुक और जांजगीर में नवाबरा पुरंदीप में जा रही कर आपस में टकरा गई।

डीजीपी- आईजीपी कॉन्फ्रेंस: नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक बड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंधित

राज्य और केन्द्र के बीच समन्वय और सूचना साझा करने पर रहेगा विशेष जोर

इस संबंध में कलेक्टर ने

आदेश जारी कर दिया

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी- आईजीपी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सुबह 5 से रात्रि 12 बजे तक नवा रायपुर के सभी मार्गों में मध्यम और भारी वाहन का प्रवेश और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में देशभर के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुख, नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी, केन्द्रीय सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राज्य और केन्द्र के ■ शेष पृष्ठ 6

नक्सलवाद खत्म करने पर रहेगा जोर



उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि अपने साल मार्च में देश से नक्सलवाद का खान्सा कर दिया जाएगा। देश में अखिला इच्छासूत्र राज्य देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है जहां इच्छासूत्र सबसे अधिक प्रभाव है। यही कारण है कि राज्य में होने वाली नक्सल बरातों पर केन्द्र की नजर भी रहती है। यहां होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद के खान्से पर चर्चा और मंत्र्य सैन तब माना जा रहा है।

अब बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी शीतलहर की चेतावनी

अचानक तापमान में उतार-चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी-जुकाम और वायरल फीवर बढ़ने की संभावना, स्वास्थ्य अमला अलर्ट

बिलासपुर/नवप्रदेश। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज से ठंड बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अचानक तापमान में उतार-चढ़ाव से हाइपोथर्मिया, सर्दी-जुकाम और वायरल फीवर का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए शीतलहर के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें, बेहद जरूरी हो तभी यात्रा करें और पूरी तरह गर्म कपड़े का उपयोग करें।

इस बढ़ते मौसम के बीच मैदानी इलाकों की स्थिति पर नजर डालें तो दुई सबसे ठंडा रहा, हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। न्यूनतम तापमान तीन



दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 15.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं रायपुर में भी न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर करीब 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम में रिकॉर्ड हुआ। खास बात यह है कि पंच दिन पहले अधिकतम का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो पिछले दस वर्षों में नवंबर में पहली बार दर्ज

किया गया इतना कम स्तर है। नवंबर का महीना आमोदर पर छत्तीसगढ़ (और आस-पास के इलाकों) में खुले और साफ मौसम वाला होता है। कभी-कभी आसमान थोड़ा बादलों से ढका भी रहता है। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे दिन का तापमान कम होने लगता है। यानी दिन हल्के ठंडे हो जाते हैं। इस समय हवाएं आमतौर पर धीमी और हल्की चलती हैं। अगर इस महीने बारिश होती भी है, तो वह सामान्यतः किसी चक्रवात या निम्न दबाव के कारण होती है जो अधिकतर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनकर इस क्षेत्र की ओर आते हैं। आमतौर पर नवंबर का महीना तुफानों और ओलापाटु जैसी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है। इसलिए यह शांत और स्थिर मौसम का महीना माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में

नवंबर महीने में ठंड का रिकॉर्ड

नवंबर महीना छत्तीसगढ़ में आमतौर पर ठंड की शुरुआत का समय होता है, लेकिन मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि कभी यह महीना कड़वा ठंडा ठंड लेकर आया तो कभी तेज गर्मी और बारिश का गढ़ाव भी रहा। मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक अक्टूबर के अंतुष्ट 2 नवंबर 1935 को अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं, 22 नवंबर 1883 को सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था जो अब तक नवंबर महीने की सबसे ठंडा रात मानी जाती है। नवंबर में सबसे ज्यादा बारिश 1924 में हुई थी, जब पूरे महीने में 138.2 मिमी की बारिश दर्ज की गई थी। इसका ही जवाब, 2 नवंबर 1930 को 24 घंटे के भीतर 70.4 मिमी बारिश हुई थी जो इस महीने के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एकदिवसीय वर्षा रिकॉर्ड है।

मलेरिया फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में दिन का तापमान लगातार प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। वहीं सूरज डूबते ही तापमान में गिरावट देखने को

मिल रहा है। ऐसे में ऑफिस जाने वाले, स्कूली बच्चों को गर्म कपड़े साथ रखें चाहिए। ताकि अचानक तापमान गिरने का असर तबीयत पर न पड़े।

न्यूज गैलरी

नाबालिंग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार



बिलासपुर/नवप्रदेश। नाबालिंग से छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को सीओ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को चारों तरफ से जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पीछाछाड़ अपने पिता के साथ 25 नवंबर को थाना उड्डिखरि रिपोर्ट दर्ज कराया कि पीछाछाड़ 23 नवंबर के दोपहर करीब 02.30 बजे घर में सोई थी उसी समय ग्राम धनिया के योगेश शर्मा के द्वारा घर अंदर घुस कर गलत निपट से पीछाछाड़ के साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट पर थाना सीओ ने अपराध कायम कर निवेदन में लिया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को हलाल से अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छेड़छाड़ के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश पर, थाना प्रभारी सीओ के द्वारा टीम तैयार कर आरोपी की पता सूची कर आरोपी योगेश शर्मा को गिरफ्तार किया कर नाबालिंग रिपोर्ट पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में सीओ पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।

डीपी विप्र और कृषि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को संविधान की शपथ दिलाई गई

संविधान को दैनिक जीवन में अपनाने और उसके सिद्धांतों पर चलने युवाओं को दी गई प्रेरणा

बिलासपुर/नवप्रदेश। डीपी विप्र कॉलेज बिलासपुर में 26 नवंबर को संविधान दिवस बड़े ही उत्साह, गरिमा और प्रेरणापूर्ण वातावरण में मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा लोक प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्वयंसेवक, प्राध्यापक और कॉलेज प्रशासन शामिल हुए। समारोह की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई, जिसके बाद पूरे सभागार में राष्ट्रगान की गूंज ने देशभक्ति का भाव जगाया।



बर्जस अंग्रेजी शाला में मनाया गया संविधान दिवस
संविधान हमें अपने कर्तव्यों के साथ जीवन के अंदरूनी मूल्यों को सिखाता है भारत का संविधान अखंड भारत की नींव है जिसमें सभी वर्ग के लोग स्वतंत्रता के साथ मिलजुलकर रहते हैं उक्त संविधान शाला की प्राचार्या निराला हवा दास ने कहा। स्वामीय बर्जस अंग्रेजी शाला में संविधान दिवस पर विशेष सभा का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय संविधान पर चर्चा हुई और कबी से प्रश्नोत्तरी की गई। इस अवसर पर शाला के बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया विभिन्न प्रदर्शनों में संविधान की जानकारी दी गई वहां की शिक्षिका आर पद्म, एक शिष्टाचार, की ओ कोनर, पी बासिमन, नंदिता पोतल, रीमा मसीह आदि ने अपने विचार व्यक्त किया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की।

समाने सष्ट किया। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों और आज के

समाज में उनके व्यावहारिक महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं युवाओं को संविधान को दैनिक जीवन में अपनाने और उसके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। हमारे राष्ट्र के मूल चरित्र, उद्देश्य और आदर्शों का संविधान दिवस अत्यंत गहरा योगदान है। प्रस्तावना न केवल संविधान की प्रस्ताविका भूमिका निभाती है, बल्कि यह उस भावना, दर्शन और उद्देश्य का भी व्यक्त करती है, जिसके आधार पर भारत जैसे विशाल, विविधभाषी और लोकतांत्रिक राष्ट्र को निर्माण हुआ है। यह नागरिकों को यह समझाती है कि भारत किन मूल्यों पर संरक्षित है और राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए कैसा समाज निर्मित करना है। प्रस्तावना की शुरुआत 'हम, भारत के लोग...' शब्दों से होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।

कृषि महाविद्यालय में अधिष्ठाता डॉ. चौर ने संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई



बैरिस्टर उमरु छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, बिलासपुर में अधिष्ठाता डॉ. एन.के. चौर ने मुख्य अतिथि के रूप में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं, प्राध्यापक, वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. चौर ने सभी उपस्थित जनों को समझाती है कि भारत किन मूल्यों पर संरक्षित है और राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के लिए कैसा समाज निर्मित करना है। प्रस्तावना की शुरुआत 'हम, भारत के लोग...' शब्दों से होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है।

के प्रति अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के सिद्धांतों जैसे की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बहुल्य के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है। संविधानिक मूल्यों की जानकारी देना के हर नागरिक को हो, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। डॉ. चौर ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका पुण्यस्मरण किया। आज के नागरिकों में माहौलधारण के प्राध्यापक, वैज्ञानिक, छात्र-छात्राएं एवं कर्मचारियों बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हाईकोर्ट ने कहा-बेटी की कन्यादान करना हिंदू पिता की नैतिक जिम्मेदारी

अविवाहित बेटी को पिता से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार, शिक्षक पिता की अपील खारिज

बिलासपुर/नवप्रदेश। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय के अनावाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने कहा कि अविवाहित बेटी की देखभाल, भरण-पोषण और शादी का खर्च उठाने से पिता की ज़िम्मेदारी नहीं रहती। कोर्ट ने सारा कहा कि बेटी का पालन-पोषण, शिक्षा और शादी का खर्च उठाना पिता का पवित्र कर्तव्य है, जिससे वह उनका रीढ़ का सहारा बन सकता है। कन्यादान हिंदू पिता का नैतिक जिम्मेदारी है। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षक पिता की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने बेटी को हर माह 2500 रूपय भरण-पोषण और शादी के लिए 5 लाख रूपय देने का आदेश दिया था। दरअसल, सऊजन को 25 वर्षीय



अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता पिता: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पुराने सेटी हिलाक संजय सेटी केस में दिए गए फैसले को जिक्र करते हुए कहा कि एक पिता अपनी अविवाहित बेटीयों की देखभाल की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। भरण-पोषण करने और उनके खर्च। जिसमें उनकी शिक्षा और विवाह पर खर्च का ध्यान रखने का कर्तव्य और दायित्व है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में पिता की ओर से आवाहन दिया गया कि हर माह भरण-पोषण देना और शादी के लिए 5 लाख 3 माह के भीतर जमा कर देगा।

सूची में फैमिली कोर्ट में फैमिली कोर्ट में परिवार प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया कि गया था कि मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब वह अपनी पहली बेटी का ध्यान नहीं रखते। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक है और हर महीने 44,642 रूपय वेतन पाते हैं। बेटी ने कोर्ट से हिंदू

सुविधा

साढ़े 7 लाख का अवैध धान जप्त

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिला प्रशासन को अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जा रहा है। कार्रवाई के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य निगराण अफसर कुन्डू ने बताया कि पांचों समर्थनों के बन्ने 533 बोरे (240 क्विंटल) धान जप्त किया गया है। राखस विभाग के नेतृत्व में खाद्य एवं मण्डी विभाग के

अधिकारियों से बनी टीम द्वारा छापे की कार्रवाई की गई। इनमें बिहार के रूपचंद किराना स्टोर में 113 बोरे (45 क्विंटल) धान, ग्राम गोलरी के ओम ट्रेडर्स से 188 बोरे (75 क्विंटल), कोटा में गुप्त ट्रेडर्स से 110 बोरे (44 क्विंटल) धान, तलपूर के गंगाधर की दुकान पर 77 बोरे धान (30 क्विंटल) तथा रागीयों के दुर्गा ट्रेडर्स में 115 बोरे (46) क्विंटल अवैध रूप से भण्डारित किये गये धान जप्त किया गया है। इसे बिहारकर में अब तक लगभग 20 लाख रूपय के अवैध धान जप्त किया गया है। अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिला पंचायत की बैठक 1 दिसम्बर को

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिला पंचायत की बैठक 1 दिसम्बर को आहूत की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सुर्वेचंद्र करी। सामान्य सभा की बैठक में खनिज विभाग, महिला वन विभाग, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, सहायक अनुसंधान आदिवासी विभाग अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

डीएलएस में किया गया संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

बिलासपुर/नवप्रदेश। कार्यक्रम में महाविद्यालय की चेयरमैन निता बर्तन शर्मा की उपस्थिति में प्राचार्य डॉ. प्रताप पाण्डेय के द्वारा संविधान के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उसकी प्रस्तावना का वाचन कराया गया। इस अवसर पर विनायक शर्मा, सतीश शर्मा, संजय उमेश जाधव, सीईओ राकेश दौलत, कार्यक्रम अधिकारी रोह अमरौरी (बालक वर्ग), मिमानी निवारी (बालिका वर्ग), डॉ. सुनीता द्विवेदी, डॉ. निता बेनर, डॉ. संजय दुबे, डॉ. विजय, कैमल, डॉ. धमा निपाटी, राजेश सिंह, डॉ. प्रीती



मिश्रा, नाजनीन गुप्त, डॉ. अर्चना पाण्डेय, डॉ. मुक्ता कुमारी, रवेला जायसवाल, चैतना शर्मा, आकांक्षा शर्मा, वर्षा श्रीवास, डॉ. सुमित दुबे, मिनी गुप्ता, मिर्नु

धान खरीदी : समर्थन मूल्य से किसानों को मिल रही राहत

धान उपार्जन केंद्रों में बेहतर व्यवस्था से किसानों में उत्साह



किस्तर धान के साथ गन्नागोप उपार्जन केंद्र पहुँचे। उन्होंने बताया कि मंडी में प्रवेश से सहयोगी रवेला धान उपार्जन केंद्र को विशेष

रूप से किसान सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। स्वच्छ पर्यावरण, छपा में बैठने की व्यवस्था, पीडू और व्यवस्था पर निगराण, ड्रा सुविधाओं ने किसानों की धन्यता और विश्वास दोनों कम की है। उन्होंने कहा कि केंद्रों परले की तुलना में कम की क्योंकि अर्न्तगत टेक्निक सुविधा के कारण हर किसान को उसके क्रम के अनुसार बुलाया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीणों के एक और किसान धन्य कर गहलने ने कहा कि वे छोटे किसान हैं इस वर्ष उन्होंने 11 क्विंटल धान बेचा है। धान बेचने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।

यात्रियों को अधिक सुगम, सुरक्षित व आरामदायक यात्रा अनुभव करने स्टेशन पुनर्विकास कार्य प्रगति बढ़

स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार व बुकिंग काउंटर आज से अस्थायी रूप से रहेगी बंद



कार्यों को तेजी देने के उद्देश्य से बिलासपुर मंडल का द्वितीय प्रवेश द्वार एवं बुकिंग काउंटर को 27 नवंबर से अस्थायी रूप से बंद किया जा

रहा है। पुनर्विकास कार्य के इस चरण में द्वितीय प्रवेश द्वार स्टेशन को जोड़ने वाली फूट ओवरब्रिज में मौजूद निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे

यात्रियों की आवाजाही को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवधि के दौरान यात्रियों से अनुरोध है कि वे मुख्य प्रवेश द्वार सील्ट उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश द्वार एवं अन्य बुकिंग काउंटरों का उपयोग करें तथा स्टेशन परिसर में लगाए गए दिशा-सूचक बोर्डों और तैल्ये कर्मियों के मार्गदर्शन का पालन करें। रेल प्रशासन यात्रियों को होने वाली शिफारिश का निराकरण के लिए खेद व्यक्त करता है एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा करता है।

बिलासपुर मंडल में पेंशन अदातल 15 दिसम्बर को

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पेंशन अदातल का आयोजन बरि मंडल कार्मिक अधिकारी समाकष बिलासपुर में 15 दिसम्बर (सोमवार) को प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। मंडल के सम्पन्न सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन द्वा प्रेष में पूर्ण दस्तावेजों के साथ (जिसमें पी.एफ.नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि, पी.पी.ओ.नम्बर एवं पता लिखना अनिवार्य है) 5 दिसम्बर (शुक्रवार) तक या उसके पूर्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदातल) को आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पेंशन अदातल में पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला कक्षा निपटन एवं पेंशन भूगतान सम्बन्धी कोई भी शिकायत है तो वे अतः आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

कोशिश रहेगी। इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाने वाली कृषि और किसानों के अथक परिश्रम का मूल्य देने में छत्तीसगढ़ सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के किसानों के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और मुस्कान लाने सरकार का भीरीय प्रयास सफल हो रहा है।

देखी गई।
प्रधान राष्ट्रीय अस्मिता का...
थे कि संविधान के माध्यम से हमारा
और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित
यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती
दशक में हमारी संसद ने जन
में को अभिव्यक्त करने के अत्यंत
गहरण प्रस्तुत किए हैं।



घोषित किया गया। उनके प्रभावशाली 3000 रुपए के लिए कुर्तै, 3000 रुपए का नाद पुरस्कार और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्कूल प्रबंधन और संस्थापन ने टीमों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी और इस प्रतिष्ठित अंतर-विद्यालयीन कार्यक्रम में मैत्री विद्या निकेतन के उनके सहायक प्रतिनिधित्व की सराहना की।

डोंगरगांव क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन के तुगलकी निर्देशों से किसानों में भारी आक्रोश

कलेक्टर का तुगलकी फ़रमान — समिति प्रबंधकों को अनावरी रिपोर्ट के आधार पर प्रति एकड़ केवल 15 से 17 क्विंटल धान खरीदने का निर्देश

किसानों में गहरा असंतोष, खरीदी केंद्रों में हड़कप

डोंगरगांव/नवप्रदेश। जिला पंचायत सदस्य एवं जिला कमीशन के अध्यक्ष राजनंदराव (अग्रणी) के महामंत्री व जिला पंचायत सदस्य महेश यादव सदस्य ने एक प्रेस विज्ञापि जारी करते हुए कहा कि भाजपा की विष्णु देव सायं सरकार में किसानों को पेरानाई लगाकर बड़ी जा रही है।

आज राजनंदराव कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव द्वारा धान खरीदी केंद्रों

का निरीक्षण कर बंद कमरे में समिति प्रबंधकों को यह मौखिक निर्देश दिया गया कि अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसानों से प्रति एकड़ केवल 15 से 17 क्विंटल धान खरीदी जाए। इस तुगलकी आदेश ने किसानों में तीव्र गुण पैदा कर दिया है।

श्री यादव ने कहा—जब-जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है, किसानों को किसी न किसी आदेश और दमनात्मक प्रक्रिया के जरिए परेशान किया जाता है। कलेक्टर का यह निर्देश दर्शाता है कि सरकार की



मंशा किसानों का पूरा धान खरीदने की नहीं है, बल्कि बढ़ते बनावर को उठाते प्रतिष्ठित किया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि कमीस की भूसा क्वेल सरकार में किसानों को सम्मान, न्याय और उनकी उन्नत का पूरा मूल्य मिलता था। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में किसानों को खरीफ फसल के लिए मजबूरी में किसानों को खरीफा

खेपों दोनूनी कीमत पर निजी हथों से खरीदना पड़ा। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया—कई किसानों की उन्नत प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक होती है। क्या सरकार कलेक्टर के इस फ़रमान के अनुसार किसानों की पूरी उन्नत खरीदी? या फिर किसानों को 15-17 क्विंटल तक सीमित कर दिया जाएगा?

उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद कई किसानों ने फेर कर अपनी पेरानाई बंद। मौके पर पहुँचने पर एक किसान ने बताया कि

उम्मीद 2 एकड़ 31 डिस्मिल से खरीदना पड़ा। उन्होंने कहा—यह किसानों के साथ खुला अन्याय है। सरकार की घोषणा के अनुसार पूर्ण क्विंटल धान की खरीदी अनिवार्य है। यदि किसानों का हक छीन गया तो मैं क्षेत्र के किसानों के साथ सहज पर उल्लंघन संस्था करने के लिए बाध्य हो जाऊँगा।

लंबित महंगाई भत्ता हेतु एक मांग एक मंच के कोर गुप की बैठक

धमतरी/नवप्रदेश। जिलासद राज्य के कमजोरी एवं पेशानों को 1 जनवरी 2025 से हटा हुआ 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं जनवरी 2017 से लिए गए महंगाई भत्ता के परिपूर्य यहि की एक सुनियं मांग को समर्थन देने वाले कर्मचारी संघटनों के प्रांतियक एवं प्रतिनिधियों को बैठक 24 नवंबर को दुर्गमधी भवन में करण सिंह अट्टे रिया द्वारा आयोजित की गई बैठक प्रमुख रूप से अर्जुन खड्ग प्रांतिय संयोगक कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा/जितेंद्र सिंह ठाकुर/कांग्रेस/प्रदेश कांग्रेस/जिला पंचायत/संयुक्त कर्मचारी अट्टे/राज्य प्रांतियक खलीसमह अधिकारी कर्मचारी संघ/महेश सिंह एवं अन्य महजालीन कर्मचारी संघ के अधिकारिक पवन साहू

मंजालीन कर्मचारी संघ/राज्य कुशी उज्जियथ था। धमतरी शासकीय दीक्षा अधिकारी महाराथ के एवं संयुक्त मोर्चा के जिला संयोगक कर्मचारी ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक मांग एक मंच को जिला एवं बंकीत तहसील स्तर पर सक्षिय करने के लिए प्रत्येक जिला में इस मांग को समर्थन देने वाला संघटन के जिलाध्यक्षों का एक का एक जिला कोर गुप गठित किया जाएगा। सत्यम संघटन के प्रांतियक अपने अपने संघक जिला एवं प्रांतिय पधिकारियों की सुची भी अट्टे रिया की के बहुरसअपर में 30 नवंबर तक जकर पोस्ट करेगा।छात्रीसमूह शासन के मुख्य सचिव विकास शील से प्रांतियध मंडल आगामी दिवसक माह के प्रथम सप्ताह में मिलकर चर्चा करेगा।

स्वामी आत्मानंद स्कूल गरियाबंद में हर्षाभास के साथ मनाया गया 75वां संविधान दिवस



गरियाबंद/नवप्रदेश। स्वामी आत्मानंद शासकीय उल्कट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गरियाबंद में आज 75वां संविधान दिवस बड़े ही गरियामय और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीमा कंवर (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद), बी.आर. साहू (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद) तथा यशवंत वासनीकर (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फ़स्ट ट्रेक, गरियाबंद) रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके उपरांत मुख्य अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया तथा यह संकेतपु लिया गया कि सभी अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। मुख्य अतिथि सीमा कंवर ने अपने उद्घोष में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद बी.आर. साहू ने कहा कि संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है, जबकि संविधान बने से पहले समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा और अन्य अधिकारों से वंचित रखा जाता था।

नगर पालिका अध्यक्ष ने किया मितानिन बहनों का सम्मान



डोंगरगांव/नवप्रदेश। मितानिन दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंरे के हार्दिक धन की मितानिन बहनों का सम्मान किया गया। इस दौरान अध्यक्ष श्री डोंरे ने सभी मितानिन बहनों को शाल श्रीफल एवं साड़ी देकर सम्मान करते हुए कहा कि सरकार और जनता के बीच मितानिन ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें हमारे नगरों पर सरकार की योजनाओं की जानकारी आना जनता तक पहुँचाती है और हमस रहते उन्हें लाभ दिलाने के लिए अमम कार्य करते आ रही है। यही नहीं दिन हो या रात मितानिन बहने किसी भी परिस्थिति में जनता को स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए कार्य करती हैं। ज्ञात हो कि नगर पालिका चुनाव के दौरान अध्यक्ष रमन डोंरे ने सभी मितानिन बहनों को एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान करने की बात कही थी जिस पर उन्होंने आज फलत करते हुए क्षेत्र की लगभग 50 से 60 मितानिन बहनों का सम्मान कर अपने कार्य के प्रति छोटा सा संकेत देने का संदेश दिया है।

धान खरीदी के केंद्रों में पारदर्शिता रखने सुगमता से धान खरीदी के लिए निर्देश

खैरागढ़/नवप्रदेश। कलेक्टर इंदरजीत सिंह चंदवाल ने कलेक्टर सरकार में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिला अधिकारियों से विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने हर विभाग को तत्प समय-समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रहे धान खरीदी केंद्रों की प्रगति, तीव्र व्यवस्था, सार उपलब्धता, पकिटन प्रबंधन, ठेकान वितरण प्रणाली, भुगतान प्रक्रिया एवं खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जाए। तथा किसानों को किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होने चाहिए। भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध हो, भीड़ प्रबंधन सुचारु रहे और प्रत्येक केंद्र का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाए।

प्रभारी सीईओ पर वसूली, फर्जी बिल और भुगतान रोकने के गंभीर आरोप

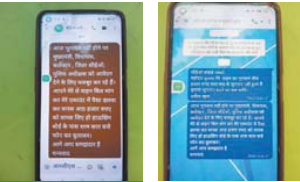
छुरा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का बम फूटा



8 हजार रुपए वापस लेने का सनसनीखेज आरोप

इस पूरे मामले में सबसे चौकाने वाला आरोप यह है कि पहले उन्हे खाते में पशि डकलवां गई और बाद में हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास शाम करीब 7 बजे बुलाकर उसमें से 8 हजार रुपए नकद वापस ले लिए गए। वाहन मालिक का कहना है कि यह खुली वसूली है, जिसे कथित तौर पर नीकरी और ठेके के खेल की तरह अंजाम दिया जा रहा है।

मजबूरी में उन्होंने प्रभारी सीईओ सतीष चन्दवरी को बहुरसअपर और मोबाइल मैजिस्ट्रेट भेजकर भुगतान की गुहार लगाई। उन्होंने साफलिखा कि यदि बहुरस भुगतान नहीं हुआ तो वे मुख्यांजी, विधाक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को रिक्कात करेगा। इसके बाद भी भुगतान तो नहीं हुआ, उन्हा उनका मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया। शरीफ खान के अनुसार



8 हजार रुपए वापस लेने का सनसनीखेज आरोप

इस पूरे मामले में सबसे चौकाने वाला आरोप यह है कि पहले उन्हे खाते में पशि डकलवां गई और बाद में हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास शाम करीब 7 बजे बुलाकर उसमें से 8 हजार रुपए नकद वापस ले लिए गए। वाहन मालिक का कहना है कि यह खुली वसूली है, जिसे कथित तौर पर नीकरी और ठेके के खेल की तरह अंजाम दिया जा रहा है।

मजबूरी में उन्होंने प्रभारी सीईओ सतीष चन्दवरी को बहुरसअपर और मोबाइल मैजिस्ट्रेट भेजकर भुगतान की गुहार लगाई। उन्होंने साफलिखा कि यदि बहुरस भुगतान नहीं हुआ तो वे मुख्यांजी, विधाक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को रिक्कात करेगा। इसके बाद भी भुगतान तो नहीं हुआ, उन्हा उनका मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया। शरीफ खान के अनुसार

राजनीतिक संरक्षण की छाया?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सूर्य बताते हैं कि जिला पंचायत के सीईओ ने इस पूरे मामले में आरुढ़, आदिवासी विकास विभाग, रायपुर को दखलक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया था। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। चर्चा है कि प्रभारी सीईओ को पद पर बैठने में एक प्रभावशाली मंत्री के निजी सचिव की भूमिका रही है, जिसके चलते जिला कलेक्टर से लेकर मंत्रालय स्तर तक अधिकारी खुलकर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं।

मोबाइल बंद, लंबी छुट्टी!

जब मीडिया ने इस पूरे मामले में प्रभारी सीईओ सतीष चन्दवरी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनका मोबाइल लगातार बंद मिला। जनपद पंचायत कार्यालय से बताया गया कि वे 'लंबी छुट्टी' हैं। सवाल यह है कि जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे?

लोकतंत्र और प्रशासन की साख दान पर

यह पूरा मामला अब केवल एक वाहन भुगतान का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, सत्ता संरक्षण और भ्रष्टाचार के गडबोड़ का प्रतीक बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि आरोप लगे हैं—सवाल यह है कि इन आरोपों पर कार्रवाई कब होगी? अब निर्णायक मुख्यांजी कार्यालय, जिला प्रशासन और पंचायत विभाग पर टिकी है। यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ संदेश जाएगा कि कानून से बड़ा सत्ता का संरक्षण है।

कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जनपद आकास पछड़ रही है—क्या छुरा पंचायत का भेष और छा जनपद पंचायत अब भ्रष्टाचार का सुनिश्चित अड्ड बन चुका है?

हड़ताल खत्म होते ही नए ऑपरेटरों की छुट्टी, बेरोजगार युवा फिर सड़क पर

■ धान खरीदी अर्थात सेवाएँ जारी रखने की मांग तेज

गरियाबंद/नवप्रदेश। जिले के उपायन केंद्रों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के दौरान प्रशासन ने तात्कालिक व्यवस्था के तहत बेरोजगार युवाओं की अस्थायी रूप से ऑपरेटर की नियुद्धा सीपी भी। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए इन युवाओं ने पूरी तत्परता से डेटा एंट्री, खरीद अद्यतन और तकनीकी कार्यों का संचालन किया। उन्हें मौखिक रूप से यह परामर्श भी दिलाया गया था कि धान खरीदी योजना के दौरान उनकी सेवा निरंतर जारी रहेगी। यही जैसी ही हड़ताल आरंभित काम पर लौटे, प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के नवजुनियुक्त युवाओं को कार्यभार पर दिया। अचानक लिए गए इस फैसले से नाराज युवा बुधवार 26 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा अधिकारियों के समक्ष रखी।



धान खरीदी तक सेवा जारी रखने की मांग

युवाओं का कहना है कि उपायन केंद्रों में नए लघात नवहस्त से कार्य कर रहे हैं। कई केंद्रों में डेटा एंट्री और खरीद संबंधी कार्य पूर्णतः ठहर गये हैं। हड़ताल के बीच प्रशासन ने परामर्श दिया था कि खरीदी अवधि तक उनकी सेवाएँ जारी रखनी चाहिए। लेकिन हड़ताल समाप्त होने के बाद भी युवाओं का रास्ता दिक्कत में है। युवाओं ने कलेक्टर से मांग की कि पूर्व दिए गए आदेश और मौखिक निर्देशों के अनुसार पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए तथा धान खरीदी अवधि तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। अचानक सेवा समाप्त होने से वे एक बार फिर बेरोजगारी की स्थिति में पहुँच गए हैं।

प्रशासन की कार्रवाई पर युवाओं में रोष

कलेक्टर को सीए गए आग्रह में युवाओं ने कहा कि प्रशासनिक आधारभूत पर परामर्श करते हुए उन्हे पूरी तृप्ति से काम किया, परंतु अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जो असरम अन्याय है। युवाओं का कहना है कि जब तक उन्हा न्यायिक समामान नहीं होता, वे अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे।

तीन सवारी वाले दुपहिया वाहनो पर पुलिस कार्यवाही



खैरागढ़/नवप्रदेश।

जिले में बाइको में तीन सवारी चलने वाली पर सखी बरतते जिला पुलिस ने अधिधान चलाकर कार्यवाही करते वाहन चालकों पर सखी बरती है। पिछले 12 दिनों में दोपहिया वाहन में तीन सवारी वाहन चलते पाए जाने पर वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 57 प्रकरणों में 12600/- रूपये का जुर्माना करने भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शाह सहीत बाबा भी अलग अलग चौक चौराहों पर आकस्मिक सफा नदर चेकिंग पकड़ लाकार तीन सवारी चोटर साफकल चलाते वाहो के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत जालकों पर चालानी कार्रवाई जारी है, वाहनो में एच एच आर पी नंबर लेटे अनिवार्य रूप से लगाने वाहनचालकों को जामकल किया जा रहा है।

रोहत 40 से अधिक मरीज हुए डिस्चार्ज, लोगों में दहशत का माहौल

नया करेला में डायरिया का प्रकोप, इलाज के बाद मिली राहत

खैरागढ़/नवप्रदेश। क्वाक के नया करेला में तीन दिन से खुर्यरी पीडितों को इलाज के बाद राहत मिलनी शुरू हो गई है। मंगलवार को स्थानीय स्थितिल अस्पताल में लगभग 52 से अधिक मरीज खुर्यरी से पीडित होकर इलाज के इच्छी भर्ती किए गए हैं। जिसमें से इलाज के बाद स्वास्थ्य सुधार होते ही बुधवार को 39 मरीजों को ड्यूटी देकर घर भेज दिया गया। स्थितिल अस्पताल में स्थितिल 8 मरीज और बुधवार को एक नए मरीज कोका इलाज जारी है। राजनंदराव जिला विकाससालय भेजे गए पांच मरीज भी बेहतर स्थिति में हैं। नया करेला के एक



ही गली में बसे खाई में 23 नवंबर से खुर्यरी के मरीज इलाज शुरू हुए हैं। जो मंगलवार को बहुरस 52 तक पहुँच गए थे। मंगलवार

पाइपलाइन से दूषित पानी कारण

स्थितिल अस्पताल के बीएमओ डा. विवेक बिसेन ने बताया कि नया करेला में एक ही गली में डायरिया पीडित सामाने आए हैं। उस गली में सफाई वाली पाइपलाइन में रिकेज से गंदे पानी की सफाई को फिहालत कारण माना जा रहा है। जाकरी की बाद लोकस्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को सूचना दी गई है वे जांच कर रहे हैं। पानी टंकी से सफाई भी रोकनी गई है। लोगों को निजी बोर से पर्यवलत आपूर्ति का उपयोग करने कहा गया है। इधर ग्रामीणों ने पाइपलाइन और टंकी की निर्माण सफाई नहीं करने पर पीएचई और पंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सफाई में लापरवाही करने, अर्थात् पानी की सफाई होने से डायरिया बढते का अंदेशा जताया है। डा. बिसेन ने बताया कि गांव में घर घर संपर्क कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों की जांच से जुटे हैं। खराब स्थिति गंभीर होकर जा रहा है। फिहालत स्थिति सामान्य होने लगी है।



बाधमारा व शिलांग में केन्द्रीय की योजनाओं की व्यापक समीक्षा

केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का तीन दिवसीय आधिकारिक दौरा शुरू, लोगों तक लाभ समय पर मिले सुनिश्चित करने पर जोर

बिलासपुर/नवप्रदेश। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले के बाधमारा में अपने तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे की शुरुआत की। बाधमारा हेलीपैड पर उनके आगमन पर उपमुख्य, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के तहत, श्री साहू ने बाधमारा संविभक्त हाउस में विभिन्न क्षेत्रों के विभागाध्यक्षों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति और चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। श्री साहू ने कहा कि विकास पहेली में गति, शहरी चुनौतियों का समाधान और विभागीय लक्ष्यों को केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। 'दोहरा बाद श्री



साहू शिलांग पहुंचे, जहाँ उन्होंने मेघालय, बैठक में सचिव एवं आयुक्त विजय कुमार, सचिवालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। विभिन्न मंत्रालयों के मिशन निदेशक और

आवास, सुरक्षा व सामुदायिक सशक्तिकरण पर फोकस

दौरे के दौरान श्री साहू ने कई परियोजना स्थलों का निरीक्षण किया, जिनमें शामिल है डेपल हलजिब कॉमन्सिक्स: निर्माणधीन कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की तथा समय-अवरोधों की पहचान के निदेश दिए। पीएलएमआई-अर्बन लमार्गी तमगु: एक लमार्गी के घर पहुँचकर योजना से प्राप्त से रहे प्रत्यक्ष लाभों और जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का आकलन किया। बीएलएम बॉर्डर आउटफोरे: सुरक्षा अवरोधना का निरीक्षण करते हुए फैलात जंगलों से संवाद किया और ऊपरी अवरोधनाओं पर चर्चा की। स्वयं सहायता समूह: स्थानीय महिला समूहों से मिलकर उनके आजीवनिक प्रयासों, उपलब्धियों और चुनौतियों को जान तब उनके सत आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया।

वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, विशेषकर शहरी विकास पहेली के क्रियान्वयन की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान-योजनाओं के

पूर्वार्त के समय विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई

श्री साहू ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्णतः देश में सुविधा, समृद्धि और तैय विकास सुनिश्चिता करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य प्रशासन, जिला अधिकारियों और स्थितिक रिक्तियों को दृष्टि दिए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि बहु-क्षेत्रीय विचार के लिए परिहार समन्वय और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

न्यूज गैलरी

जिला कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय संविधान दिवस



बिलासपुर/नवप्रदेश। जिला कार्यालय बिलासपुर में आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करने का सबसे संकल्प लिया। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया था। जिसको बाद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अपर कलेक्टर सुशी ज्योति पटेल ने जिला कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाया। शासन के निर्देशानुसार अन्य जिला कार्यालयों में भी संविधान दिवस मनाया गया।

संविधान से पहले शिक्षा विभाग में नहीं थे शिक्षाकर्मी हाईकोर्ट ने कहा- क्रमोन्नति के लिए पात्र नहीं; 1188 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज

बिलासपुर/नवप्रदेश। हाईकोर्ट ने 10 साल सेवा अधि के बाद शिक्षकों की क्रमोन्नति की मांग वाली 1188 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके ज्यस ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान से पहले शिक्षाकर्मी स्थूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे। इसलिए उन्हें क्रमोन्नति पाने की पात्रता नहीं है।

दरअसल, पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षाकर्मी ग्रेड-3, 2 और 1 का शिक्षा विभाग में संविधान किया गया। इसके बाद उन्हें सहायक शिक्षक (एलबी), शिक्षक (एलबी) और व्याख्याता (एलबी) पददान दिया गया। लेकिन, इन शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, जिस पर पटेल ने 1188 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लाई। इसमें कहा गया कि वे 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद क्रमोन्नति के हकदार हैं।



संविधान नीति के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता

याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सोना साहू मामले का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सोना साहू केस के तथ्य पूरी तरह अलग हैं, इसलिए समानता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान नीति 30 जून 2018 में सार है कि पूर्ण शिक्षाकर्मी केवल संविधान की तारीख में ही शासकीय शिक्षक माने जाएंगे और उससे पहले के किसी भी लाभ, वेतन वृद्धि या क्रमोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता।

लेकिन विभाग ने 2017 का यह अंदेश वेतनवृद्धि (क्रमोन्नति) देने की बात कही लागू नहीं किया, जिसमें 10 साल बाद

में हाईकोर्ट के शिजीवन बेंच के फैसले के आधार पर क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई है, दौरान राज्य शासन की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी ग्रेड-3/सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त हुए थे और उनकी सेवा व नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन था। ऐसे में उन्हें संविधान से पहले राज्य शासन का नियमित सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता। वे क्रमोन्नति देने के लिए 10 मार्च 2017 को जारी समूहों के आदेश्यक मन्तव्य पुरी नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवा अधि की गणना केवल 1 जुलाई 2018 यानी संविधान की तारीख से ही की जा सकती है। इसी के चलते वे 10 वर्ष की अतिरिक्त योग्यता पुरी ही नहीं करते। हाईकोर्ट ने शासन के इन तर्कों को सही माना है।

श्री सप्तशती वैभव लक्ष्मी का हुआ हवन-पूजन



बिलासपुर/नवप्रदेश। श्री सप्तशती वैभव लक्ष्मी का जप 6 माहों से हर शुक्रवार को, श्री साईं कृपा हॉस्पिटल, सरजू, बगीचा रोड, तेलीपारा चल रहा है। सभी साधक एक साथ माता को नमस्कार करते हैं, आवाहन करते हैं, आवाहन के बाद माता का श्रृंगार होता है फिर एक साथ सामूहिक जप 701 मंत्रों का होता है और अंत में अर्चना होती है, समापन में उनके खीर का भोग लगाया जाता है। माता को कनकहासा भी कहा जाता है, वह कनक के अमर पर विराजमान होती है और उनके हाथों में कनक शृंगार रहता है। माता का जप सभी साधक अमरगुप्त पुरी ही नहीं करते। हाईकोर्ट ने शासन के इन तर्कों को सही माना है।

पीएमश्री स्कूल मल्हार में हंगामा: छात्र की मौत ने खोल दी अव्यवस्था की पोल

विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन

मल्हार/नवप्रदेश। पीएमश्री स्कूल जवाहर नवींद्र विद्यालय मल्हार में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का धैर्य बुधवार सुबह टूट गया। एक दिन पहले बीमार पड़े छात्र की मौत ने पूरे परिसर को अंदर तक हिला दिया और इसी गुस्से ने आज स्कूल गेट के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया। छात्रों का कहना है कि बीमार छात्र को समय पर उचित इलाज नहीं मिला और मौत की यह घटना किसी सामान्य चूक का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही लापरवाही और कमजोर प्रबंधन व्यवस्था का परिणाम है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आग्रह लगाया है कि हाईकोर्ट और स्कूल परिसर में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, समस्याओं को खार-बार बताने के बावजूद प्रबंधन चुनौती से घुस रहा है और कई बार बच्चों से ऐसे काम करवाए जाते हैं, जो उनकी पहुंच और दिनचर्या के खिलाफ हैं। छात्राओं ने भी बहदुरी से सामने आकर कहा कि कैपस में निगरानी व्यवस्था बेहद



दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुबह 8 बजे पर जमा हुए छात्रों ने मारेजाओं करते हुए मांग की कि मौत की पूरी जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और स्कूल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन खुलकर जवाबदेही तय नहीं करेगा और सुधार की ठोस पहल नहीं होगी, उनका विरोध जारी रहेगा। घटना की सुचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन छात्रों का आक्रोश और मांग नहीं ले रहा।

कमजोर है और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की गंभीर कमी है। उनका आरोप है कि मौत से जुड़े मामला टीसी गैर-जिम्मेदारी की देन है, जिसे अब किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्कूल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जबकि परिसर

महिला आयोग की सुनवाई 28 को

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 28 नवंबर 2025 को प्रार्थना भवन में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य पॉइंट महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सुनवाई में बिलासपुर जिले से प्राप्त पॉइंट महिलाओं के आवेदन और शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

जिला कार्यालय में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिला कार्यालय बिलासपुर में आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करने का सबसे संकल्प लिया। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। जिसको बाद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अपर कलेक्टर सुशी ज्योति पटेल ने जिला कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के



समक्ष उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाया। शासन के निर्देशानुसार अन्य जिला कार्यालयों में भी संविधान दिवस मनाया गया।

कलेक्टर ने अनोखे अंदाज में किया बीएलओ का सम्मान

मॉल में पसंदीदा फिल्म दिखाने के साथ कराया सपरिवार लंच

बिलासपुर/नवप्रदेश। महात्मा गांधी के विशेष गहन पुरोहिण कार्यक्रम के तहत उल्फट करवाते कार्य पर तबलुर्ब बर्बक के ग्राम केवलपान की बीएलओ दायत धुव को कलेक्टर संजय आशुल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत डिजिटलईजेशन का कार्य पूरा किया। आज बीएलओ दायत धुव को पुरस्कार स्वरूप परियारा सलित मेमेटो मॉल में फिल्म दिखाने और लंच की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। दायत धुव ने बताया कि उनके क्षेत्र के



एंट्री के साथ समया पर पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि गांव में बाहर से आई बहुओं के डेटा एक्शन करने के प्राथमिक कठिनाई आई, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी समझाने के बाद

इससे उनका संपूर्ण कार्य समय पर पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वे अपना कार्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से किया जिससे लक्ष्य पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा सम्मानित किए जाने पर वे बहुत खुश हैं और मौलानिस्त महसूस कर रहे हैं। साथ ही पुरस्कार स्वरूप परियारा सलित फिल्म देखने और लंच ने उनके उसका को और अधिक बढ़ा दिया है, भविष्य में भी अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव में उन्होंने 120 बहदुर फिल्म का आनंद लिया।

समूह की महिलाओं ने संविधान दिवस मनाया



बिल्हा/नवप्रदेश। संविधान दिवस पर आज 26 नवंबर को नगर पंचायत बिल्हा द्वारा साहू की महिलाओं द्वारा वाई क्रमोंक 3 अग्रसर वाई में संविधान दिवस मनाया गया। साहू के मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। भारत के मूल संविधान जैसे न्याय

निरिक्षण

महात्मा गांधी उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, बिल्हा हथनी पंचायत दुर्ग के कुलसचिव ने किया निरीक्षण

उद्यानिकी व वानिकी से जुड़े छात्रों को तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान से पूर्ण करना प्राथमिकता: कैरम

बिलासपुर/नवप्रदेश। बिल्हा हथनी महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव वरसंत कैरम ने आज विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालय बिल्हा हथनी का निरीक्षण किया। उनके साथ डीन डॉ. तोरप लाल साहू भी उपस्थित थे। इस दौरान कुलसचिव ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान कार्यों तथा प्रायोगिक क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य उपस्थित थे, जिसमें सूरजा कुमार, सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा) एवं लैंडस्केप



आर्किटेक्चर, पौधाजाल फंजन, सारक प्राध्यापक (सब्जी विज्ञान), डॉ. प्रवेश गिरी गोस्वामी, अतिथि शिक्षक (पशु चिकित्सा एवं पशु रोग विज्ञान), डॉ. यामिनी सिन्हा, अतिथि शिक्षक (सब्जी विज्ञान), डॉ. रणित कुमार, अतिथि

शिक्षकों से शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता, व्यवहारिक कलाओं और सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर कुलसचिव ने महाविद्यालय के कार्यों की समालोचना करते हुए छात्रों को तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान से पूर्ण करना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निर्वहन करने तथा विद्यार्थियों के समक्ष विकास के लिए प्रेरित किया। दौरा सकारात्मक रूप से पूरा हुआ और संकाय सदस्यों द्वारा कुलसचिव एवं डीन का आभार व्यक्त किया गया।

छत्तीसगढ़ राइज सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी, 238 पदों पर होगी भर्ती

■ 1 दिसंबर से भर्तियां आरंभ

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य की विभिन्न सेवाओं में कुल 238 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

2024 में 246 पदों के लिए नोटिफिकेशन था, इस वर्ष 238 पदों के साथ भर्ती जारी की गई है। यह संख्या पिछले कई वर्षों की तरह लगभग 200-250 के पर्यक में बनी हुई है, जिससे राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की निरंतर मांग दिखती है।

आयु सीमा, आरक्षण व अन्य पात्रता

- आयु सीमा (सामान्य वर्ग के लिए) - 1 जनवरी 2025 को 21 से 30 वर्ष
- छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (35 + 5 साल छूट)
- अन्य आरक्षित श्रेणियां- अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार, विधवा/

परिवर्तक, भूतपूर्व सैनिक, दिवंगा, निरामृतसार अतिरिक्त आयु छूट दी गई है।
● रीशेषांक घोषणा: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। अंतिम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा घोषित न हुआ हो तो भी प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा तक डिग्री अनिवार्य होगी।

इस बार सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के लिए हैं, जो राज्यस्य एवं आगदा प्रबंधन विभाग से संबंधित होंगे। इसके बाद 29

पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा 'ग'), और 12 पद राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) के लिए आए हैं।



अन्य महत्वपूर्ण पद

- मुख्य नगर पालिका अधिकारी (कक्षा 'ख') : 18 पद
- छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सेवा अधिकारी: 15 पद
- छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (उप जिलाधिकारी): 14 पद
- राज्य कर निरीक्षक: 16 पद
- उप पंजीयक: 12 पद
- आबकारी उप-निरीक्षक: 11 पद
- राज्य कर सहायक आयुक्त: 10 पद

चयन प्रक्रिया

- परीक्षा तीन चरणों में

- अभ्यर्थित की जाएगी
- प्रारंभिक परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) - दो पहर: सामान्य अध्ययन और योग्यता परीक्षा, वस्तुनिष्ठ आधार पर।
- मुख्य परीक्षा- वर्णनात्मक पेपर, भाषा (हिंदी/अंग्रेजी/छत्तीसगढ़ी), निबंध, सामान्य अध्ययन सहित विविध विषय।
- साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण- लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के आधार पर कुल अंक 1500 में से उम्मीदवारों का चयन होगा।
- पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि राज्य सेवा परीक्षा में पदों की संख्या में

आवेदन तिथि व परीक्षा की रूपरेखा

- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 1 दिसंबर 2025, दोपहर 12:00 बजे
- आवेदन की अंतिम तिथि: 30 दिसंबर 2025, रात्रि 11:59 बजे
- नूटि सुधार : 31 दिसंबर (मुस्त) - 2 जनवरी 2026
- सशुल्क नूटि सुधार: 3 - 5 जनवरी 2026 (500 शुल्क)
- प्रारंभिक परीक्षा की

- संचालित तिथि: 22 फरवरी 2026 (सुबह 10:00-12:00 दोपहर 3:00-5:00 बजे)
- मुख्य परीक्षा की संचालित तिथि: 16, 17, 18 एवं 19 मार्च 2026
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार के डाक या मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

उत्तर-चढ़ाव राह है। वर्ष 2015 में सर्वाधिक 352 पदों की भर्ती हुई थी, जबकि

कोविड वर्ष 2020-21 में 171-175 पदों तक संख्या घट गई थी।

27 नवंबर से रायपुर की रोड पर वन-वे होगा लागू

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर में वन रोड काई चोक पर रस्तेय और गहर लाईनच का काम शुरू होगा। इसके लिए शास्त्री चौक से मेकाहारा, मस्टीलेवल पार्किंग और जयसभा चौक जाने वाली सड़क 27 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक महिने के लिए बंद हो जाएगी।

शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक वन-वे होगा लागू

प्रशासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। पहले शास्त्री चौक से मस्टीलेवल पार्किंग तक जयसभा चौक जाने वाली सड़क 15 दिन तक बंद हो जाएगी।

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सड़क के बंद हो जाने के बाद सड़क पर पयोग संख्या में परेसिडेंटियल बेरिकेड्स लगाकर बंद करेगी। वाहनों को परेसिडेंटियल कने एवं यातायात संचालन के लिए पयोग संख्या में गार्ड्स की व्यवस्था करेगी। वहीं बंद सड़क के शुरुआत और अंत में वन वे का सूचना बूट लगाया अनिवार्य है।

भारी वाहन चालकों की आंखों की हेमो गी जांच

पिछले साल छह दिन चला था यह अभियान

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाते की संचालन है। पिछले साल यह अभियान 23 से 28 दिसंबर तक नेशनल हाइवे पर स्थित ठोला प्लाना कर चलाया था। इसी स्थानों पर ड्राइवर्स की आंखों की जांच की गई थी। चरम बंद लगाने पर सामान्य नंबर का चरमा मौक पर दिया गया। वहीं गंभीर समस्या होने पर ऑइडर अस्पताल सित्त बड़े चिकित्सालयों में भर्ती कर इलाज किया गया। बिन जिलों में ठोला प्लाना है, वहां 5 नंबर सहायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सुबह 10 से राया 4 बजे तक नंबर परीक्षण किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले नंबर परीक्षण में सभी ड्राइवर कवर नहीं गए थे। जांचकारों के अनुसार ड्राइवर्स की आंखों की जांच साल में कम से चार से पांच बार होनी चाहिए। दरअसल कई ड्राइवर की आंखें कमजोर होती हैं। इस कारण भी सड़क दुर्घटना होती है। उन्हें चरमे लगाने की भी जरूरत होती है, वे भी नहीं लगाने। कई ड्राइवर्स को कलर विजन की समस्या होती है। ऐसे में वे कलर नहीं पहचान पाते। सिमल का कलर नहीं पहचानने से भी दुर्घटना हो सकती है। नंबर गेज विशेषज्ञों के अनुसार जांच या इससे अधिक उम्र के लोगों को सालाना में एक बार आंख की जांच जरूर करनी चाहिए।

गैंगस्टर सुनील को प्रोडक्शन वॉरंट पर झारखंड से लाकर पूछताछ करेगी पुलिस

रायपुर/नवप्रदेश। झारखंड की जेल में बंद गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मरके सिंह को रायपुर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी। उसे प्रोडक्शन वॉरंट पर 10 दिसंबर को लाने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। आरोपी सुनील जुलाई 2024 में तेतीबांधा स्थित पीआरए एच के दरबार में हथ डूब आदेश मामले में मृत्युदण्ड आर्पित है। इस घटना में गैंगस्टर अमन साब के शूटिंग में आर्पिस के बाहर फर्मागि की थी। बता दें कि अमन को अप्रैल 2024 में प्रोडक्शन वॉरंट पर रायपुर लाया गया था। झारखंड की पुलिस को वॉरंट पर आने की कोशिश करने और पुलिस दल पर हमला के दौरान मुठभेड़ में सह मारा गया था। इसके बाद गंग गंग को सुनील अदालत कर रहा था। इंटरपोल की मदद से अजयजीवन में गिरफ्तार करने के बाद लेल भेजा गया है। सुनील को इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉस विरुद्ध का आरोपी माना जाता है और अमन एवं लॉस नेटवर्क के बीच कड़ी के रूप में काम करने के मुठभेड़ में मिले हैं। उक्त सभी के संबंध में रायपुर पुलिस पूछताछ करेगी।

टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ भर्ती के लिए आवेदन 8 तक

रायपुर/नवप्रदेश। हिंदुस्तान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टॉफ भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 8 दिसंबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें टीचिंग में स्कर्म प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर के 13, असिस्टेंट प्रोफेसर के 29 पदों में भर्ती की जाएगी। वहीं, नॉन टीचिंग में फर्लने आर्किट के 1, असिस्टेंट लैबोरेरियन के 1 पद, सिल्टम मैनेजर के 1, परसोनल सेक्रेटरी के 1, असिस्टेंट ग्रेड 2 के 1, खब इंजीनियर फिलिल के 1, खब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 1, अकाउंट्स असिस्टेंट के 1, मस्टीनीडिया डिप्लोमर के 1, स्पेसिअल असिस्टेंट काम जेन इंफ्रक्टर सेल और फीमेल के 1-1, ड्राइवर के 3, आर्पिस असिस्टेंट के 2, गाईडर कम अटेंडेंट के दो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है।

मुद्रण-लेखन सामग्री विभाग के पदों की परीक्षा 30 को

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश-पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 30 नवंबर को सुबह 11 बजे से 12.15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के जरिए विभाग के कपी होल्डर, प्लेट मेकर, प्रेसिंग मशीन ऑपरेटर, सफ्ट डिजिटल डिप्टर ऑपरेटर, कनिष्ठ मिलान कलर मशीन ऑपरेटर, फिल कलर सीटिंग डिप्टर ऑपरेटर, ट्रेसर रिटचर/पेक्टर, जूनियर रिडर के लिए पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा होगी। अभ्यर्थी व्यापक की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के संबंध में कटिवाई होती है तो हेल्पलाइन 07712972780 एवं 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं।

सहायिकाओं, प्रकाशक एवं मुद्रण प्रमाण प्राप्त होना चाहिए। शोध नंबर 74, सेक्टर-11, उत्तर इंडस्ट्रियल परिया रायपुर, से मुद्रित कर तृतीय तल, सुगर मार्केट कॉम्पलेक्स, राजा चतुर्वास सिंह स्टडीयम के सामने अग्रगण्य को, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2015/62431, सायादक-बन्दरगोश्वरी (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए उत्तरागरी), स्थानीय सायादक-डिक्कम सिंह ठाकुर, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbilaspu01@gmail.com

796 बकायादारों के जीपीएस से काटे गए कनेक्शन, मचा हड़कंप

रायपुर/बिलासपुर/रायपुर/नव प्रदेश। विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद स्मार्ट हो गया है। पहले बकायादारों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के लिए घर-घर घूमना पड़ता था। ओएण्डएम सफल के तीनों डिब्बेजन के 796 बकायादारों के विद्युत कनेक्शन सीधे जीपीएस से ऑफिस से काट दिए गए। इससे बकायादारों में हड़कंप मच गया। 260 पहुंचकर बकाया बिल का भुगतान किया। तब उनके कनेक्शन जोड़े गए।

सोमवार को सुबह 10 बजे एक स्थान ओएण्डएम सफल के तीनों डिब्बेजन के 796 बकायादारों के घर और दुकानों की बिजली सीधे जीपीएस के माध्यम से रायपुर स्थित स्मार्ट मीटर के सखर रूप से काट दिया गया। इसके साथ ही बकायादारों के प्रतिष्ठानों की बिजली सप्लाई उभ हो गई। कनेक्शन कटने के साथ ही बकायादारों में हड़कंप मच गया। उनके द्वारा बिजली ऑफिस से संपर्क किया गया। वहां जाने के बाद उनको बकाया राशि का भुगतान करने के बाद विद्युत



एक ही दिन में हुई 28 लाख रुपए की बकाया वसूली

विद्युत वितरण कंपनी के ओएण्डएम डिब्बेजन के तीनों डिब्बेजन बिलासपुर, मुसली और पेड़ुम में स्मार्ट मीटरों से बकायादारों से मीटर काटने के बाद पहले ही दिन दो से साठ उपभोक्ताओं ने 28 लाख रुपए की वसूली हुई। वहीं सौर बकायादारों की विद्युत कनेक्शन बिल भुगतान के बाद जोड़े जाएगी बिना भुगतान जोड़ने पर उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा।

कनेक्शन जोड़ने की बात कही गई

पहले ही दिन 260 बकायादारों ने बिजली ऑफिस पहुंचकर बिजली बिल का भुगतान किया। इसके बाद उनका विद्युत कनेक्शन बहाल कर दिया गया। कंपनी द्वारा पिछले साल करीब चौदह सौ बकायादारों के विद्युत कनेक्शन जीपीएस से पिछले

साल काटे गए थे। इस साल पहली बार उक्त तरीके से बकायादारों बिजली बंद किए गए हैं। ज्ञात हो कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के स्थान पर नया स्मार्ट मीटर लागू जा रहा है। यह मीटर जीपीएस से ऑनरेट होता है। उसमें कई सुविधाएं हैं। उपभोक्ताओं के घर में अगर बिज

कनेक्शन काटने से पहले तीन दिन दिया गया अल्टीमेटम

विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर वाले बकायादारों की बिजली सीधे नहीं काटी जा रही है। खंबे समय तक बिल का भुगतान नहीं करने पर उनको तीन दिनों तक लगातार एसएमएस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी उनके द्वारा बिल भुगतान नहीं करने पर उनको तीन दिनों तक लगातार एसएमएस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी उनके द्वारा बिल भुगतान नहीं करने पर उनको तीन दिनों तक लगातार एसएमएस भेजा जा रहा है। इसके बाद भी उनके द्वारा बिल भुगतान नहीं करने पर उनको तीन दिनों तक लगातार एसएमएस भेजा जा रहा है।

रीडिंग दर्ज कर बिजली बिल जारी किया जा सकता है। साथ ही मीटर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सिस्टम एलर्ट कर देता है। वहीं

कनेक्शन काटने से पहले तीन दिन दिया गया अल्टीमेटम

रायपुर रेलवे स्टेशन पर खुलेगा एजीक्यूटिव पेड लाउंज, हेल्दी फूड कैफे, स्वास्थ्य समेत वाई-फाई और चार्जिंग सुविधा भी

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर रेलवे स्टेशन से सड़क करने वाले यात्रियों के लिए राहत भी खबर है। अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने एजीक्यूटिव पेड लाउंज के लिए टेंडर फ्लाल कर दिया है। स्टेशन पर यह सुविधा एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर खुलेगा एजीक्यूटिव पेड लाउंज, मिलेगी कई सुविधाएं

एजीक्यूटिव पेड लाउंज को एक पट्टे के लिए 30 और दो पट्टे के लिए 60 रुपए देने होंगे। यह लाउंज पूरा सह वातावरण होगा, जिसमें आयुष्यक एनीमोमीटर कुर्सियां, टीवी, खाने पीने की व्यवस्था, वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।



इसके अलावा यात्री यहां योग और ध्यान भी कर सकेंगे। हेल्दी डिश और हेल्दी फूड कैफे भी लाउंज का हिस्सा होंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टेंडर फ्लाल हो गया है और कंपनी जल्द काम संपन्न लेगी। यह लाउंज प्लेटफॉर्म 1 पर बनाया जा रहा है।

मीड से मिलेगी राहत

रायपुर स्टेशन वाइड-वर्ल्ड आर्ट्स का प्रमुख स्टेशन है। वहां फार पेटिंग होता है। दो एंथे और दो नौवा लोकी-डिजल बूट 1200 तक वजन सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रेलवेको ने यात्रियों की संख्या 70 हजार से बढ़कर एक लाख तक पहुंचा जा रही है, जिसके कारण पेटिंग होल अवरल मच जाती है। ट्रेने लेने लेने गए यात्री जगह-जगह बैठने को जगहू से जाते हैं।

कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए दीपेन्द्र की रिमांड 5 तक बढ़ी

रायपुर/नवप्रदेश। कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए दीपेन्द्र चावड़ा की न्यायिक रिमांड को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

इंओड्रक्यू के फि र श न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। आरोपी को इंओड्रक्यू ने मिलिंग घोटाले में 2000 करोड़ रुपए वसूली कर उसे रिफिंडे में शामिल किया था। तब पहुंचने के आरोप में 12 तिमांवर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि घोटाले में परवरी

2025 में तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी और रोशन चन्दावर के खिलाफ विशेष को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

इंओड्रक्यू के फि र श न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। आरोपी को इंओड्रक्यू ने मिलिंग घोटाले में 2000 करोड़ रुपए वसूली कर उसे रिफिंडे में शामिल किया था। तब पहुंचने के आरोप में 12 तिमांवर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि घोटाले में परवरी

न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। इस प्रकरण में मनोज सोनी और रोशन चन्दावर को जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं पूर्व इंओड्रक्यू अफिल ट्रेडिंग एवं कारोबारी अमन देवर के खिलाफ विवेचना चल रही है।